आकाशवाणी शिमला

18.12.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन में शुरू–मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में ई–विधान एप्लीकेशन नेवा का किया शुभारम्भ।
- भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को घेरा–सतापक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक।
- भाजपा ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ धर्मशाला में निकाली जनआक्रोश रैली–नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के भुंतर, गग्गल और शिमला हवाई अड्डे को कृषि उड़ान योजना के तहत किया गया चिन्हित।

शीतकालीन सत्र

प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर तपोवन में शुरू हुआ। 21 दिसम्बर तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में ई–विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारम्भ किया। तपोवन परिसर नेवा से जुड़ने के बाद प्रदेश विधानसभा की तमाम कार्यवाही को देश के किसी भी कोने से देखा जा सकता है।

*प्रदेश विधानसभा का तपोवन परिसर आज नेशनल ई–विधान एप्लीकेशन नेवा से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेवा के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि जहाँ आज पूरा विश्व टैक्नोलॉजी के माध्यम से अदभुत विकास कर रहा है वहीं हमारा देश व प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाकर हम राष्ट्र स्तर पर पहुंच गए हैं और अब प्रदेश विधानसभा की कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश टैक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी राज्य रहा है और प्रदेश की ई–विधान प्रणाली का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का ये प्रोजैक्ट अभी केवल तपोवन विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ है और शिमला विधानसभा के लिए भी डीपीआर तैयार कर केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है।*

*इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश विधानसभा 2010 में ई–विधान प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा थी। उन्होंने कहा कि अब एक दशक के बाद केन्द्र की मदद से नेवा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है जिससे प्रदेश को फायदा होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेवा व्यवस्था लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिचायक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ई–विधान की तर्ज पर नेवा का भी प्रदेश को लाभ मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए धर्मशाला से मैं रितेश कपूर...*

## नियम–67

प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज विपक्ष ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से घेरा। इस दौरान सदन में कई बार सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने एक–दूसरे के खिलाफ भारी शोरगुल किया और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को कई बार हस्तक्षेप करने के बाद एक मौके पर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। भाजपा के रणधीर शर्मा ने सदन की बैठक के शुरू होते ही नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव का मुद्दा उठाया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और सदन में आज के लिए निर्धारित तमाम कार्यों को लंबित करते हुए इस प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ कर दी। काम रोको प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विपक्षी दल भाजपा ने हाल ही में राज्यपाल को कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सौंपे गए आरोप पत्र में उठाए गए मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि विपक्ष काम रोको प्रस्ताव को लेकर गम्भीर नहीं है। मुख्यमंत्री ने नादौन में जमीन खरीद–फरोख्त को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी स्पष्टीकरण दिया और कहा कि एचआरटीसी को बेची गई जमीन की भाजपा जो कीमत बता रही है, वह वर्ष 2015 की है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 80 कनाल जमीन 4 लाख 75 हजार रुपए स्टांप ड्यूटी देकर दो करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि इस जमीन की खरीद–फरोख्त में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा के बीच हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राज्य को व्यवस्था पतन की ओर ले जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सुक्खू सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति से राजस्व में छह से सात फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के समय शराब से राजस्व में 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। जयराम ठाकुर ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार द्वारा चार विधेयक पेश करने पर भी कड़ा एतराज जताया और कहा कि नियम 67 के तहत चर्चा के दौरान किसी भी अन्य कामकाज की अनुमति की इजाजत का नियमों में प्रावधान नहीं है।

## विधेयक

प्रदेश में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों ग्रेड–2 का जल्द ही राज्य कॉडर होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद कानून में संशोधन होगा। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में कनिष्ठ पुलिस अधिकारी व न्यायवादियों को भी शामिल किया जा सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व न्यायवादियों के उपलब्ध न होने की वजह से कई जिलों में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित नहीं हो सके हैं।

हमीरपुर जिले के भोटा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राधा स्वामी सत्संग ब्यास जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से अधिक भूमि को हस्तांतरित कर सकेगा।

भाजपा रैली

भाजपा ने आज धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनआक्रोश रैली निकाली। इस अवसर पर रैली को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो साल में जो कारनामे किए हैं इसका दोष भाजपा पर मढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को 5 साल में रोजगार देने का वायदा करने वाली सुक्खू सरकार दो साल में रोजगार देने में नाकाम रही है और सरकार की दो साल में एक भी उपलब्धि नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है और प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हो गए हैं।

जनआक्रोश रैली को सांसद राजीव भारद्वाज पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर, सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने भी सम्बोधित किया।

इंदु गोस्वामी

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के भुंतर, गग्गल और शिमला हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के तहत चिन्हित किया है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुरलीधर मोहोल ने बताया कि इन हवाई अड्डों को पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को प्रभावी और निर्बाध तरीके से मण्डियों तक पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डों को चुना गया है। इंदु गोस्वामी के एक अन्य सवाल के जवाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार ने नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चम्बा, हमीरपुर और सिरमौर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा है कि सीसीपीए ने 13 नवम्बर 2024 को कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं ताकि कोचिंग केन्द्रों के झूठे या भ्रामक दावों पर रोक लगाई जा सके। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार द्वारा संसद में कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम संबंधी उठाए गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। बी.एल. वर्मा ने बताया कि सीसीपीए में भ्रामक विज्ञापन के लिए विभिन्न कोचिंग केन्द्रों को 45 नोटिस जारी किए हैं और 19 कोचिंग संस्थानों पर 61 लाख 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।